

## बिहार गज़ट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 282)

1 वैशाख 1932 (श0) पटना, बुधवार, 21 अप्रील 2010

सं0 ए/नि0भू०सं0/टेकनी(38)—14/2008—264 कृषि विभाग

संकल्प

18 मार्च 2010

विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों द्वारा कार्यान्वित जलछाजन विकास कार्यक्रम के विगत वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग, भारत सरकार के पहल पर विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से राष्ट्रीय वर्षाश्रित क्षेत्र प्राधिकार (एन०आर०ए०ए०), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से वर्षा पर आधारित कृषि हेतु जलछाजन विकास परियोजनाओं के लिये सामान्य गाइड लाईन प्राप्त है जो दिनांक 1 अप्रील 2008 से प्रभावी है। उक्त गाइड लाइन के कंडिका 4.4 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी गठित करने का निदेश दिया गया है।

उक्त निदेश के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रुप में बिहार वाटर शेड डेवलपमेंट सोसाईटी का गठन करने का निर्णय निम्नप्रकार लिया गया है:—

(1) विकास आयुक्त, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग	उपाध्यक्ष
(3) प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
(4) प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
(5) प्रधान सचिव / सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन	सदस्य
विभाग।	

- (6) प्रधान सचिव, लध्रुजल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सदस्य
- (7) प्रधान सचिव,विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना सदस्य
- (8) प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना सदस्य

(9) प्रधान सचिव / सचिव, पंचायती राज सदस्य

(10) कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार, सदस्य

पूसा (समस्तीपुर)।

(11) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना सदस्य

(12) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल पषर्द, पटना सदस्य

(13) तकनीकी विशेषज्ञ, एन०आर०ए०ए०, नई दिल्ली सदस्य

(14) प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बी०डब्लू०डी०एस० सदस्य सचिव

सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

बिहार वाटर शेड डेवलपमेंट सोसाइटी के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगें:-

- (1) ब्लॉक तथा जिला स्तर पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर राज्य के लिए वाटरशेड विकास की संदर्शी तथा कार्यनीतिक योजना तैयार करना और कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति तथा प्रत्याशित उपलब्धियों / परिणामों, वित्तीय परिव्ययों को सूचित करना तथा मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए विभाग में केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी से सम्पर्क करना।
- (2) राज्यों को स्वीकृत निधियों से राज्य स्तरीय आंकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करना तथा इसका रख–रखाव करना और राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा केन्द्र के साथ इसे ऑन लाइन जोड़ना ।
- (3) पूरे राज्य में जिला वाटरशेड विकास इकाइयों (डी०डब्ल्यू०डी०यू०) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- (4) राज्य के भीतर विभिन्न भागीदारों के क्षमता निर्माण के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की एक सूची अनुमोदित करना और एन0आर0ए0ए0 / नोडल मंत्रालय के परामर्श से समग्र क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति तैयार करना।
- (5) समुचित विषयनिष्ठ चयन मानदण्डों तथा पारदर्शी प्रणालियों को अपनाकर डी०डब्ल्यू०डी०यू०/जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिज्ञात/चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित करना।
- (6) विभिन्न स्तरों (आंतरिक एवं बाह्य / स्वतंत्र प्रणालियों) पर निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन प्रणालियाँ स्थापित करना।
- (7) केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी के सहयोग से राज्य में वाटरशेड पिरयोजनाओं की नियमित तथा गुणवत्तापूर्ण ऑन लाइन मोनीटिरिंग सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र एवं सक्षम एजेंसियों के साथ साझेदारी विकसित करके सूचना प्राप्त करना।
- (8) राज्य के भीतर सभी वाटरशेंड परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र संस्थागत मूल्यांकनकत्ताओं की एक सूची (पैनल) तैयार करना, इस सूची को केन्द्र स्तर पर संबंधित नोडल एजेंसियों से विधिवत रुप से अनुमोदित करवाना तथा यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन का कार्य नियमित आधार पर किया जाता है।
- (9) नोडल मंत्रालय / एन०आर०ए०ए० के साथ समन्वय से राज्य विशिष्ट प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रौद्योगिकी मैनुअल आदि तैयार करना तथा इन्हें लागू करना।
- (10) सोसाइटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कार्य।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक—एक प्रति संबंधित विभागों एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय तथा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

> बिहार—राज्यपाल के आदेश से, ए० के० सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 282-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in